<https://hi.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9B%E0%A5%87%E0%A4%A6_%E0%A5%A9%E0%A5%AD%E0%A5%A6&oldid=4296740>

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 एक ऐसा लेख था जो [जम्मू और कश्मीर](https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%9C%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A5%82_%E0%A4%94%E0%A4%B0_%E0%A4%95%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%B0) को स्वायत्तता का दर्जा देता था।[[1]](https://hi.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9B%E0%A5%87%E0%A4%A6_%E0%A5%A9%E0%A5%AD%E0%A5%A6&oldid=4296740#cite_note-1)[[2]](https://hi.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9B%E0%A5%87%E0%A4%A6_%E0%A5%A9%E0%A5%AD%E0%A5%A6&oldid=4296740#cite_note-2) संविधान के भाग XXI में लेख का मसौदा तैयार किया गया है: अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान।[[3]](https://hi.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9B%E0%A5%87%E0%A4%A6_%E0%A5%A9%E0%A5%AD%E0%A5%A6&oldid=4296740#cite_note-3) जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा को, इसकी स्थापना के बाद, भारतीय संविधान के उन लेखों की सिफारिश करने का अधिकार दिया गया था जिन्हें राज्य में लागू किया जाना चाहिए या अनुच्छेद 370 को पूरी तरह से निरस्त करना चाहिए। बाद में जम्मू-कश्मीर संविधान सभा ने राज्य के संविधान का निर्माण किया और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की सिफारिश किए बिना खुद को भंग कर दिया, इस लेख को भारतीय संविधान की एक स्थायी विशेषता माना गया।

Article 370 of the Indian Constitution was an article that gave autonomy status to Jammu and Kashmir. The article is drafted in Part XXI of the Constitution: Temporary, Transitional and Special Provisions. Jammu And the Constituent Assembly of Kashmir, after its establishment, was empowered to recommend articles of the Indian Constitution which should be implemented in the state or Article 370 should be completely repealed. Later the Jammu and Kashmir Constituent Assembly formulated the constitution of the state and dissolved itself without recommending repeal of Article 370, and then the article being considered a permanent feature of the Indian Constitution.

भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में एक ऐतिहासिक [जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019](https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%9C%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A5%82-%E0%A4%95%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%B0_%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%97%E0%A4%A0%E0%A4%A8_%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A5%87%E0%A4%AF%E0%A4%95,_%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%A7%E0%A5%AF) पेश किया जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के दो केंद्र शासित क्षेत्रों के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया । जम्मू कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र में अपनी विधायिका होगी जबकि लद्दाख बिना विधायी वाली केंद्रशासित क्षेत्र होगा।

The Government of India introduced a historic Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 in the Rajya Sabha on 5 August 2019, which proposed to remove Article 370 of the Constitution from the state of Jammu and Kashmir and to divide the state into two Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh. The Jammu and Kashmir Union Territory will have its own legislature while Ladakh will be a union territory without a legislative body.



विशेष अधिकार

Special rights

* धारा 370 के प्रावधानों के अनुसार, संसद को जम्मू-कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार है लेकिन किसी अन्य विषय से सम्बन्धित क़ानून को लागू करवाने के लिये केन्द्र को राज्य सरकार का अनुमोदन चाहिये।
* इसी विशेष दर्ज़े के कारण जम्मू-कश्मीर राज्य पर संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती।
* इस कारण राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्ख़ास्त करने का अधिकार नहीं है।
* 1976 का शहरी भूमि क़ानून जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होता।
* इसके तहत भारतीय नागरिक को विशेष अधिकार प्राप्त राज्यों के अलावा भारत में कहीं भी भूमि ख़रीदने का अधिकार है। यानी भारत के दूसरे राज्यों के लोग जम्मू-कश्मीर में ज़मीन नहीं ख़रीद सकते।
* भारतीय संविधान की धारा 360 जिसके अन्तर्गत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है, वह भी जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होती।
* जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय करना ज़्यादा बड़ी ज़रूरत थी और इस काम को अंजाम देने के लिये धारा 370 के तहत कुछ विशेष अधिकार कश्मीर की जनता को उस समय दिये गये थे। ये विशेष अधिकार निचले अनुभाग में दिये जा रहे हैं।
* According to the provisions of Article 370, Parliament has the right to make laws regarding defense, foreign affairs and communication about Jammu and Kashmir but the Center needs the approval of the state government to implement the law related to any other subject.
* Due to this special status, Article 356 of the Constitution does not apply to the state of Jammu and Kashmir.
* For this reason, the President does not have the authority to dismiss the constitution of the state.
* Urban land law of 1976 does not apply to Jammu and Kashmir.
* Under this, an Indian citizen has the right to buy land anywhere in India, except in special empowered states. That is, people of other states of India cannot buy land in Jammu and Kashmir.
* Article 360 ​​of the Constitution of India under which there is a provision for imposing financial emergency in the country also does not apply to Jammu and Kashmir.
* The merger of Jammu and Kashmir into India was a much greater necessity and to carry out this work some special rights were given to the people of Kashmir at that time under Section 370. These special rights are being given in the lower section.

धारा 370 के सम्बन्ध में कुछ विशेष बातें

Some special things about Section 370

1) धारा 370 अपने भारत के संविधान का अंग है।

2) यह धारा संविधान के 21वें भाग में समाविष्ट है जिसका शीर्षक है- ‘अस्थायी, परिवर्तनीय और विशेष प्रावधान’ (Temporary, Transitional and Special Provisions)।

3) धारा 370 के शीर्षक के शब्द हैं - *जम्मू-कश्मीर के सम्बन्ध में अस्थायी प्रावधान* (“Temporary provisions with respect to the State of Jammu and Kashmir”)।

4) धारा 370 के तहत जो प्रावधान है उनमें समय समय पर परिवर्तन किया गया है जिनका आरम्भ 1954 से हुआ। 1954 का महत्त्व इस लिये है कि 1953 में उस समय के कश्मीर के वजीर-ए-आजम [शेख़ अब्दुल्ला](https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B6%E0%A5%87%E0%A4%96%E0%A4%BC_%E0%A4%85%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A5%81%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A4%BE), जो [जवाहरलाल नेहरू](https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%9C%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%B2_%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%82) के अंतरंग मित्र थे, को गिरफ्तार कर बंदी बनाया था। ये सारे संशोधन जम्मू-कश्मीर के विधानसभा द्वारा पारित किये गये हैं।

1) Section 370 is a part of constitution of India.

2) This section is included in the 21st part of the constitution which is titled 'Temporary, Transitional and Special Provisions'.

3) The words of the title of Section 370 are - "Temporary provisions with respect to the State of Jammu and Kashmir" in relation to Jammu and Kashmir.

4) The provisions under section 370 have been changed from time to time, which started from 1954. The significance of 1954 is that in 1953, the then Wazir-e-Azam Sheikh Abdullah of Kashmir, who was an intimate friend of Jawaharlal Nehru, was arrested and imprisoned. All these amendments have been passed by the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir.

संशोधित किये हुये प्रावधान इस प्रकार के हैं-

The revised provisions are as follows:

* (अ) **1954 में** चुंगी, केंद्रीय अबकारी, नागरी उड्डयन और डाकतार विभागों के कानून और नियम जम्मू-कश्मीर को लागू किये गये।
* (A) In 1954, the laws and rules of the octroi, central abkari, civil aviation and postal service departments were implemented in Jammu and Kashmir.
* (आ) **1958 से** केन्द्रीय सेवा के आई ए एस तथा आय पी एस अधिकारियों की नियुक्तियाँ इस राज्य में होने लगीं। इसी के साथ सी ए जी (CAG) के अधिकार भी इस राज्य पर लागू हुए।
* (B) Since 1958, appointments of IAS and IPS officers of the Central Service started in this state. Along with this, the rights of CAG also came into force on this state.
* (इ) **1959 में** [भारतीय जनगणना](https://hi.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%AF_%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%97%E0%A4%A3%E0%A4%A8%E0%A4%BE&action=edit&redlink=1) का कानून जम्मू-कश्मीर पर लागू हुआ।
* (C) In 1959, the Indian Census Act came into force on Jammu and Kashmir.
* (र्ई) **1960 में** [सर्वोच्च न्यायालय](https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%89%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A4%A4%E0%A4%AE_%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AF) ने जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों को स्वीकार करना शुरू किया, उसे अधिकृत किया गया।
* (D) In 196 , the Supreme Court began accepting appeals against the decisions of the Jammu and Kashmir High Court, it was authorized.
* (उ) **1964 में** संविधान के अनुच्छेद 356 तथा 357 इस राज्य पर लागू किये गये। इस अनुच्छेदों के अनुसार जम्मू-कश्मीर में संवैधानिक व्यवस्था के गड़बड़ा जाने पर राष्ट्रपति का शासन लागू करने के अधिकार प्राप्त हुए।
* (E) In 1964, Articles 356 and 357 of the Constitution were implemented on this state. According to these paragraphs, the authority to impose the rule of the President was obtained when the constitutional system was disturbed in Jammu and Kashmir.
* (ऊ) **1965 से** श्रमिक कल्याण, श्रमिक संगठन, सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक बीमा सम्बन्धी केन्द्रीय कानून राज्य पर लागू हुए।
* (f) Since 1965, the Central Laws relating to labor welfare, labor organization, social security and social insurance came into force on the state.
* (ए) **1966 में** [लोकसभा](https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%95%E0%A4%B8%E0%A4%AD%E0%A4%BE) में प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया।
* (g) In 1966, the right to send its representative elected by direct vote in the Lok Sabha was given.
* (ऐ) **1966 में** ही जम्मू-कश्मीर की विधानसभा ने अपने संविधान में आवश्यक सुधार करते हुए- ‘प्रधानमन्त्री’ के स्थान पर ‘मुख्यमन्त्री’ तथा ‘सदर-ए-रियासत’ के स्थान पर ‘राज्यपाल’ इन पदनामों को स्वीकृत कर उन नामों का प्रयोग करने की स्वीकृति दी। ‘सदर-ए-रियासत’ का चुनाव विधानसभा द्वारा हुआ करता था, अब राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होने लगी।
* (h) It was only in 1979 that the assembly of Jammu and Kashmir made necessary reforms in its constitution - 'Chief Minister' in place of 'Prime Minister' and 'Governor' in place of 'Sadar-e-Riyasat' and approved these names and it was approved to use these names. The 'Sadar-e-Riyasat' was elected by the Legislative Assembly, and now the Governor was appointed by the President.
* (ओ) **1968 में** जम्मू-कश्मीर के उच्च न्यायालय ने चुनाव सम्बन्धी मामलों पर अपील सुनने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया।
* (i) In 1979, the High Court of Jammu and Kashmir gave the Supreme Court the right to hear appeals on election related matters.
* (औ) **1971 में** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विशिष्ट प्रकार के मामलों की सुनवाई करने का अधिकार उच्च न्यायालय को दिया गया।
* (j) In 1971, the High Court was empowered to hear specific cases under Article 226 of the Indian Constitution.
* (अं) **1986 में** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के प्रावधान जम्मू-कश्मीर पर लागू हुए।
* (k) In 1986, the provisions of Article 249 of the Indian Constitution came into force on Jammu and Kashmir.
* (अः) इस धारा में ही उसके सम्पूर्ण समाप्ति की व्यवस्था बताई गयी है। धारा 370 का उप अनुच्छेद 3 बताता है कि ‘‘पूर्ववर्ती प्रावधानों में कुछ भी लिखा हो, राष्ट्रपति प्रकट सूचना द्वारा यह घोषित कर सकते है कि यह धारा कुछ अपवादों या संशोधनों को छोड दिया जाये तो समाप्त की जा सकती है।
* (l)  It is only in this section that the system of its complete abolition is given. Sub-paragraph 3 of section 370 states that "anything written in the preceding provisions, the President may declare by express notice that this section may be abolished if certain exceptions or amendments are omitted.

इस धारा का एक परन्तुक (Proviso) भी है। वह कहता है कि इसके लिये राज्य की संविधान सभा की मान्यता चाहिये। किन्तु अब राज्य की संविधान सभा ही अस्तित्व में नहीं है। जो व्यवस्था अस्तित्व में नहीं है वह कारगर कैसे हो सकती है?

There is also a proviso of this section. It says that for this, the Constituent Assembly of the state needs recognition. But now the Constituent Assembly of the state does not exist. How can a system that does not exist be effective?

जवाहरलाल नेहरू द्वारा जम्मू-कश्मीर के एक नेता पं॰ प्रेमनाथ बजाज को 21 अगस्त 1962 में लिखे हुये पत्र से यह स्पष्ट होता है कि उनकी कल्पना में भी यही था कि कभी न कभी धारा 370 समाप्त होगी। पं॰ नेहरू ने अपने पत्र में लिखा है- ‘‘वास्तविकता तो यह है कि संविधान का यह अनुच्छेद, जो जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिलाने के लिये कारणीभूत बताया जाता है, उसके होते हुये भी कई अन्य बातें की गयी हैं और जो कुछ और किया जाना है, वह भी किया जायेगा। मुख्य सवाल तो भावना का है, उसमें दूसरी और कोई बात नहीं है। कभी-कभी भावना ही बडी महत्त्वपूर्ण सिद्ध होती है।’’

From a letter written by Jawaharlal Nehru to Pandit Premnath Bajaj, a leader of Jammu and Kashmir, on 21 August 1962, it is clear that it was in his imagination that Section 360 would be abolished at some point. Pt. Nehru wrote in his letter- "The reality is that despite this article of the constitution, which is said to be responsible for the special status of the state of Jammu and Kashmir, in spite of it, many other things have been done and whatever else is to be done will also be done. The main question is of emotion, there is nothing else in it. Sometimes emotion itself proves very important. ''

05/08/2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव रखा | जो निम्नानुसार है:-

On 05/04/2019, the Central Government proposed in Parliament to remove Article 370. Which is as follows: -

संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार की सहमति से, निम्नलिखित आदेश करते हैं: -

In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 370 of the Constitution, the President, with the consent of the State Government of Jammu and Kashmir, makes the following orders: -

* 1. इस आदेश का नाम संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू ) आदेश, 2019 है।
  2. यह तुरंत प्रवृत्त होगा और इसके बाद यह समय-समय पर यथा संसोधित संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू ) आदेश, 1954 का अधिक्रमण करेगा।

1. The name of this order is the Constitution (Applicable to Jammu and Kashmir) Order, 2019.

2. It shall come into force immediately and thereafter it shall supersede the Constitution (applicable to Jammu and Kashmir) Order, 1954, as amended from time to time.

1. समय-समय पर यथा संसोधित संविधान के सभी उपबंध जम्मू और कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में लागू होंगे और जिन अपवादों और अशोधानो के अधीन ये लागू होंगे ये निम्न प्रकार होंगे:-

2. All the provisions of the Constitution, as amended from time to time, shall apply in relation to the State of Jammu and Kashmir and the exceptions under which Ashodhano shall apply shall be as follows: -

अनुच्छेद 367 में निम्नलिखित खंड जोड़ा जायेगा, अर्थात :-

" (4) संविधान, जहाँ तक यह जम्मू और कश्मीर के सम्बन्ध में लागू है, के प्रयोजन के लिए  -

(क) इस संविधान या इसके उपबंधों के निर्देशों को, उक्त राज्य के सम्बन्ध में यथा लागू संविधान और उसके उपबंधों का निर्देश मन जायेगा;

(ख) जिस व्यक्ति को राज्य की विधान सभा की शिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जम्मू एवं कश्मीर के सदर-ए-रियासत, जो ततस्थानिक रूप से पदासीन राज्य की मंत्री परिषद् की सलाह पर कार्य कर रहे है, के रूप में ततस्थानिक रूप से  मान्यता दी गयी है, उनके लिए निर्देशों को जम्मू एवं कश्मीर के राजयपाल के लिए निर्देश मन जायेगा ।

(ग ) उक्त राज्य की सरकार के निर्देशों को, उनकी मंत्री परिषद् की सलाह पर कार्य कर रहे जम्मू एवं कश्मीर की राजयपाल की लिए निर्देशों को शामिल करता हुआ मन जायेगा; तथा

(घ) इस संविधान की अन्नुछेद 370 के परन्तुक में "खंड (2) में उल्लिखित राज्य की संविधान सभा" अभिव्यक्ति को  "राज्य की विधान सभा"  पढ़ा जायेगा।

"(4) For the purpose of the Constitution, so far as it is applicable in relation to Jammu and Kashmir, -

(A) The directions of this Constitution or its provisions shall be deemed to be the directions of the Constitution and its provisions as applicable in relation to the said State;

(B) Recognized by the President on the recommendation of the Legislative Assembly of the State as President, who is acting on the advice of the Council of Ministers of the neighboring state of Sadar-e-Riyasat, Jammu and Kashmir has gone, the instructions for them will be considered as instructions for the Governor of Jammu and Kashmir.

(C) the instructions of the Government of the said State shall be deemed to contain the instructions for the Governor of Jammu and Kashmir acting on the advice of their Council of Ministers; And

(D) The expression "Constituent Assembly of the State mentioned in clause (2)" in the proviso to Article 370 of this Constitution shall be read as "Legislative Assembly of the State"